

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर
विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 3- जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष,
समस्त स्थानीय विकास प्राधिकरण
उत्तराखण्ड।
- 5- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
देहरादून।

- 2- उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण
देहरादून/हरिद्वार/टिहरी।
- 4- सचिव,
क्षेत्र विकास प्राधिकरण
देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।

आवास अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 3 सितम्बर, 2017

विषय : भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-2013/V-आ०-2015-55(आ०)/2006टी०सी० दिनांक 08-12-2015 द्वारा द्वि० निर्देश दिये गये।

2- उक्त शासनादेश में भू-उच्चीकरण शुल्क से सम्बन्धित प्रस्तर 5.5(I)(i) में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए निम्न विवरणानुसार इस शर्त के साथ संशोधित प्राविधान एतद्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है कि ग्रीन बिल्डिंग हेत अतिरिक्त एफ०ए०आर० की अनुमति प्रदान होने के उपरांत बिल्डर द्वारा कम्प्लीशन सर्टिफिकेट्स में ग्रीन बिल्डिंग मानकों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त स्थिति में परचेवल एफ०ए०आर० का दोगुना श्रमन शुल्क लिए जाने का प्रावधान होगा।

वर्तमान प्रावधान				संशोधित प्रस्ताव				
क्र० सं०	उपयोग समूह (भूखण्ड क्षेत्रफल वर्गमीटर में)	मैदानी क्षेत्र		क्र० सं०	उपयोग समूह (भूखण्ड क्षेत्रफल वर्गमीटर में)	मैदानी क्षेत्र		
		अधिकतम भू-आच्छादन %	अनुमन्य एफ०ए०आर०			अधिकतम भू-आच्छादन %	अनुमन्य एफ०आर०	ग्रीन बिल्डिंग हेतु प्राप्त रेटिंग के आधार पर देय अतिरिक्त F.A.R
ब	मल्टीपल इकाईयों	50	2.00	ब	मल्टीपल इकाईयों	50	1.80	0.2*
स	ग्रुप हाउसिंग	35	2.10	स	ग्रुप हाउसिंग	35	1.80	सिल्वर 0.1 गोल्ड 0.2 प्लैटिनम 0.3
द	EWS Housing	50	2.00	द	EWS Housing	50	2.00	
य	Affordable Housing	50	2.40	य	Affordable Housing	50	2.10	सिल्वर 0.1 गोल्ड 0.2 प्लैटिनम 0.3

*SUBJECT TO MAXIMUM FAR 3.0 WHICH SHALL BE IN THE FORM OF PURCHASABLE FAR AS PER THE PROVISION NUMBER 5.5 (V)

* वास्तुविद द्वारा ग्रीन बिल्डिंग प्राविधान सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रमाण पत्र के आधार पर F.A.R देय होगा जिसकी पुष्टि कम्प्लीशन सर्टिफिकेट में की जायेगी।

	<p>* उक्त प्राविधान विभिन्न क्षेत्रों में लिए उपविधि के अधीन निर्धारित भवन की ऊंचाई की सीमान्तर्गत होगा।</p> <p>* ग्रीन बिल्डिंग की रेटिंग का आधार प्रमाणीकृत संख्याओं के द्वारा निर्धारित रेटिंग के अनुसार होगा।</p>
--	---

3- उक्त शासनादेश I दिनांक 08-12-2016 को केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

4- अतः कृपया उपरोक्तानुसार संशोधन को यथा आवश्यकतानुसार प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति सहित अंगीकृत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

2